चीनी उद्योग से जुड़े लोगों को सरकार दे सकती है बड़े राहत पैकेज का तोहफा

चीनी में बढ़ सकती है मिठास

सुशील मिश्र
मुंबई, 28 अप्रैल

चीनी उद्योग को राहत पैकेज मिलने की संभावनाएं बढ़ने के साथ ही चीनी में मिठास बढ़ना शुरू हो गई है। मई की शुरुआत में गन्ना मिलों को सरकार की तरफ से राहत पैकेज का तोहफा मिलना लगभग तय है। गन्ना किसानों का बकाया जल्द दिलाने की रणनीति के तहत सरकार चीनी पर लगने वाले आयात शुल्क को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। इसके साथ ही चीनी का बफर स्टॉक बनाने की भी छूट देने की तैयारी है। महज तीन कारोबारी दिनों में चीन के दाम 7 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुके हैं।

चीनी उद्योग से जुड़े लोगों को भरोसा है कि सरकार उनकी मांगों को मानते हुए जल्द ही बड़े राहत पैकेज का तोहफा देगी। सबसे पहले तो सरकार आयात शुल्क में बढ़ोतरी होने की बात कह रही है। आयात शुल्क में बढ़ोतरी होने से विदेश से आने वाली चीनी महंगी होगी जिससे भारतीय चीनी मिलें भी दाम बढ़ा सकेंगी। सरकार की तरफ से मिल रहे सकारात्मक संदेशों का असर चीनी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। वायदा बाजार में चीनी 2,700 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गई। पिछले सप्ताह खाद्य मंत्री राम विलास पासवान के बयान के बाद से चीनी में मिठास आना शुरू हो गई है। पासवान ने कहा था कि कम कीमत और ऊंची उत्पादन लागत की वजह से चीनी मिलों को पिछले कुछ वर्षों से नुकसान उठाना पड़ रहा है जिससे उन्हें किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने में दिक्कतें आ रही हैं।

वायदा बाजार में चीनी की कीमत 2,700 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गई है

हाजिर बाजार में चीनी के दाम में हल्की बढ़त देखी जा रही है। हाजिर बाजार में चीनी (एम) की कीमत चार दिन में 40 रुपये बढ़कर 2,555 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, जबकि वायदा बाजार में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। एनसीडीईएक्स पर चीनी मई अनुबंध 2,500 रुपये क्विंटल पहुंच गया जबकि 23 अप्रैल को इसकी कीमत 2,340 रुपये बोली जा रही थी। इसी तरह जुलाई अनुबंध 2,390 रुपये उछलकर 2,602 रुपये, अक्टूबर चीनी 2,667 रुपये और दिसंबर 2,705 रुपये पर पहुंच गई। चीनी की मजबूती पर वाशी मार्केट के चीनी कारोबारियों का कहना है कि महीने का अंत होने के कारण हाजिर में फिलहाल ज्यादा हलचल नहीं है लेकिन 1 मई के बाद चीनी के दामों में तेजी आना तय माना जा रहा है। कमोडिटी विशेषज्ञ राहुल राय कहते हैं कि कम उत्पादन होने की आशंका देखते हुए सरकार दलहन की स्टॉक लिमिट पहले ही खत्म कर चुकी है और अब चीनी का भी बफर स्टॉक बढ़ाने का ऐलान भी जल्द होने वाला है। इस बार गन्ने का रकबा कम होने की आशंका बढ़ रही है, साथ ही आयात शुल्क पर सरकार और मिल मालिकों के बीच चल रही बातचीत भी सकारात्मक दिशा में है जिससे बाजार में स्टॉकिस्ट सक्रिय हो रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में बढ़ रहे संकट को लेकर चिंतित सरकार गन्ना किसानों के 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान करने में हो रही परेशानी को हल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। कहा जा रहा है कि बैठक में चीनी पर आयात शुल्क मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने, बफर स्टॉक तैयार करने, ऋणों के पुनर्गठन, एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन, सफेद चीनी पर निर्यात सब्सिडी आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन मौजूद थे।

चीनी मिलों का संगठन इस्मा पिछले काफी समय से सरकार से चीनी निर्यात पर सब्सिडी दिए जाने, 20 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने और भुगतान संकट से उबरने के लिए चीनी मिलों के 36,000 करोड़ रुपये के कर्ज का पुनर्गठन करने की मांग करता रहा है। इस्मा के मुताबिक चीनी उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं।

Business Standard
29/4/15

✓N